रियासत काल में शिक्षा–एक प्रसंग

❑ चंद्रभानु भारद्वाज

औपनिवेशिक दौर में शैक्षिक पिछड़ेपन से वैसे तो सभी परिचित थे किन्तु तत्कालीन परिस्थितियों को ठोस रूप में समझना वर्तमान शैक्षिक प्रयासों की महत्ता और गुणवता की आवश्यकता को पुष्ट कर सकता है। यहां राजस्थान की भरतपुर रियासत में तत्कालीन शैक्षिक स्थिति और प्रयासों की एक झलक प्रस्तुत की गयी है। इसमें कई प्रवृत्तियों संदर्भ सहित समझ में आती हैं कि किस प्रकार अंग्रेजी सत्ता शिक्षा को अपने लिए कारकून तैयार करने के उपक्रम के रूप में देखती है ? किस तरह रियासतदानों के साथ एक 'इलीट' वर्ग उभर रहा है जो आज तक शिक्षा में अपनी बढ़त और फलत: समाज में अपना वर्चस्व बनाये हुए है ? किस तरह सार्वजनिक शिक्षा खैराती सदावर्त पर पनप रही है और बालिकाओं को कैसे इस धारा से बाहर रखा गया है ?

भरतपुर-राजपूताने की अनोखी रियासत थी; अनोखी इसलिए कि यहां के शासक आमतौर पर 'महाराजा' होते हुए भी अपेक्षाकृत उदार मूल्यों के पोषक रहे। हालांकि एक सामन्ती व्यवस्था में प्रजातांत्रिक मूल्यों की कल्पना करना असंभव है, फिर भी इस रियासत के अंतिम दो शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने शासन काल में कमोबेश ऐसे काम किए जो प्रजा के हित में थे । हालांकि ऐसे कामों में उनकी सीमाएं थीं । इन सीमाओं के अन्तर्गत अंग्रेजी हुकूमत द्वारा उन्हें ऐसे कामों के करने की मनाही थी जिनसे हकूमत की नीतियां प्रभावित हों । इन नीतियों में यदि हम केवल शिक्षा की बात करें तो अंग्रेजों ने कभी नहीं चाहा कि उनकी प्रजा को अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए प्रकारान्तर में केवल राजा और राजा के परिवार को ही अच्छी और उच्च शिक्षा दिए जाने के अधिकार थे। परिणामस्वरूप पूरी रियासत में केवल एक हाई स्कूल के अलावा कोई अन्य उच्च शिक्षा संस्थान नहीं था । यह हाई स्कूल भी रियासत की राजधानी में ही स्थापित था । शेष राज्य में मिडिल तक की ही पढ़ाई का प्रबन्ध था जिसकी परीक्षा इलाहबाद (यूपी)बोर्ड लेता था । कालान्तर में इस बोर्ड की स्थापना रियासत में की गई।

आर्थिक रूप से कमजोर रियासती शिक्षा के विकास हेतु कुछ प्रयास किए गये। ऐसे दो प्रयास थे-एक, प्रतिवर्ष महाराजा की सालगिरह के अवसर पर घोणाएं, जो भरतपुर राजपत्र के असाधारण अंकों में प्रकाशित होती थीं, जिनमें महाराजा प्रसन्न होकर जनता के उत्थान के संबंध में शिक्षा के विकास हेतु घोषणा करते थे । दूसरे, 30 मार्च 1930 को गठित केन्द्रिय सलाहकार समिति भरतपुर राज्य (सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी भरतपुर स्टेट) के प्रयासों से शिक्षा सुधार के क्षेत्र में प्रभावी प्रयास हुए । इस कमेटी में कुल 20 लोग शामिल थे जिनमें सरकारी अमले के अलावा गैर सरकारी पांच नामजद सदस्यों में बाबू राजबहादुर एमए एलएलबी, गोकुल जी वर्मा, चौधरी झग्गर खाँ मेव, लाला बैजनाथ प्रसाद, लाला नत्थीलाल वेश्य शामिल थे। इन सदस्यों में रियासत के विकास के लिए प्रबल संकल्प था। बाबू राजबहादुर और गोकुल जी वर्मा प्रजा परिषद के बैनर तले आजादी की लड़ाई में शामिल थे, वे बार बार रियासत में उत्तरदायी शासन की मांग करने लगे थे। उन्हीं के फलस्वरूप संवेंधानिक सुधारों और विकास के मद्देनजर इस सलाहकार समिति का गठन हुआ जो बाद में रियासत की असैम्बली के रूप में ब्रज जया प्रतिनिधि समिति के नाम से परिवर्तित हुई।

केन्द्रीय सलाहकार समिति की कार्यवाही में समिति के अध्यक्ष सर रिचर्ड टोटो हम (सीएसआई, सीआईई, आईसीएस) ने अपने भाषण में कहा था - ''हमने इस केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन यह समझते हुए किया है कि भारत की भारतीय रियासतों के प्रशासन/शासन में संवैधानिक सुधारों की बहुत आवश्यकता है जिनमें शिक्षा प्रमुख विषय हो सकता है।अंग्रेजी हुकूमत की जरूरत के मुताबिक ऐसे विद्यार्थी तैयार किये जाने चाहिए जो रियासतों में हुकूमत के मानदंडों के अनुरूप काम कर सकें।'' यह मानदंड क्या थे ? प्रोसीडिंग में इसका कोई जिक्र नहीं है।[1]

महाराजा की सालगिरह के अवसर पर प्रकाशित भरतपुर राजपत्र एक दिसम्बर 1943 में 'गरीबों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए प्रयास किए जाएंगे।' की घोषणा पर आरंभिक अमल दिखाई देता है। लोहागढ किले के अन्दर बिहारी जी के मंदिर में एक ऐसा स्कूल संचालित किया गया जहां अधिकांश गरीब बच्चों को प्रवेश दिया गया । इन्हें प्रवेश घोषणा के मुताबिक सदावर्त विभाग से ''पेटिया'' का प्रबन्ध किया गया था। इस पेटिया में आटा, दाल, नमक-मसाले व तेल के अतिरिक्त पांच पैसा प्रतिदिन हर बच्चे को जेब खर्च शामिल था। दादी जी साहिबा का महल भी बिहारी के मंदिर के सामने था जहां से विशेष अवसरों

पर महाराजा की सवारी निकलती थी और इस स्कूल के बच्चे पंक्ति में खड़े होकर पहला अभिवादन महाराजा को पेश करते थे।[2]

दूसरा स्कूल जो नजर आया वह था मेवात में स्थापित मेव स्कूल, जिसे पर्याप्त बच्चे न होने के कारण बन्द कर दिया गया और वहां से विस्थापित 20 बच्चों को सीकरी की प्राथमिक शाला में भर्ती कराया गया । सीकरी की यह शाला 1928 में स्थापित की गई थी। इस शाला में उर्दू, फारसी पढ़ाने का भी इन्तजाम किया गया था। दरअसल सभी रियासतों की राजभाषा उर्दू-फारसी थी, अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से प्रचलित थी । पर भरतपुर राज्य में यदि कागजातों को देखा जाए तो महाराजा कृष्णसिंह के कार्यकाल में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। यहां से प्रकाशित सरकारी अखबार 'ब्रज संदेश' इसका प्रमाण हो सकता है।

इस सीकरी शाला के बारे में तथ्य कौंसिल आफ स्टेट के प्रेसीडेंट के सीकरी कैम्प 22 अक्टूबर 1933 के इन्सपेक्शन नोट से इस प्रकार ज्ञात होते हैं । नोट में कहा गया था - ''हमने सीकरी स्कूल के निरीक्षण के समय पाया कि कुल 65 शिक्षार्थियों में से 20 मेव बच्चे हाल ही में बंद किये गये मेव स्कूल से इस स्टेट स्कूल में दाखिल किये गये हैं । मुझे मेव लम्बरदारों (प्रतिनिधियों) ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह दरख्वास्त किया है कि सीकरी स्कूल के इस प्राथमिक विद्यालय को मिडिल स्कूल में तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि पूरे मेवात की यही एक मात्र संस्था है जहां सीकरी की 2500 जनसंख्या, जिसमें सीकरी के पड़ौसी गांव मेवात सहित शामिल हैं, को शिक्षा दी जानी है। मिडिल स्कूल की इनकी मांग तर्कसंगत है। अत: एजूकेशन मेम्बर कौंसिल ऑफ स्टेट इसकी स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाऐं । मेव लम्बरदारों की यह भी प्रार्थना है कि यहां उर्दू और फारसी के अध्यापन की भी व्यवस्था की जाए । एज्युकेशन मेम्बर क्या बताएंगे कि इस तरफ वे क्या कर सकते हैं ?''[3]

रियासत के पास पर्याप्त राजस्व न होने के कारण स्कूलों का विकास संभव ही नहीं था । 1914-1919 के दौरान तीन साला राजस्व 36,01,842 रुपये में से ढाई लाख रुपये तो राजा के लिए ही पैलेस व्यय के नाम पर आवंटित था । रियासत की कुल जनसंख्या 5,58,785 में से लगभग आठ से तेरह प्रतिशत लोग ही पढ़े-लिखे माने जा सकते थे। इस आठ प्रतिशत में भी घटत बढ़त होती रहती थी। कभी-कभी यह ग्राफ काफी नीचे गिरता हुआ दिखता है ।

1943-1944 में रियासत में कुल 26 सरकारी स्कूल थे, 9 अनुदानित स्कूल थे और 28 ऐसे स्कूल थे जिनको कोई भी अनुदान नहीं मिलता था।

लेकिन तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट में कहा गया था कि रियासत में कुल 1397 गांव थे जिनमें टाउन भी शामिल थे, गांव के हिसाब से स्कूलों का प्रतिशत 10.88 होता है अर्थात आठ गांव या देहात पर एक स्कूल संचालित था । इन सभी विद्यालयों में 46,612 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे । यह संख्या भी कभी-कभी इतनी घट जाती थी कि कुछ स्कूलों को बन्द करना पड़ता था, घटती संख्या का कारण मलेरिया और अन्य महामारियों का प्रतिवर्ष फैलना बताया जाता था ।

बालिका साक्षरता तो लगभग नगण्य ही थी यानी राज्य में केवल 90 बालिकाएं ही शिक्षा ग्रहण कर रहीं थी अर्थात प्रतिशत लें तो 0.84 हो सकती हैं । बजट में शिक्षा पर राज्य ने 93, 381 रुपये आवंटित किये थे जिसमें कुल 82,381 रुपये खर्च हुए। इस राशि में मेयो कॉलिज अजमेर में पढ़ रहे राजकुमारों और राजसरदारों पर खर्च की गई राशि भी (6,002 रुपये) शामिल है।[4]

राज्य का एकमात्र सदर हाईस्कूल-भरतपुर ऐंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल-मिडिल स्कूल सहित मैट्रिक तक की शिक्षा देता था जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध था। एक अन्य ऍंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल डीग में स्थापित था जिसकी फाइनल परीक्षा भी वर्नाक्यूलर फाइनल परीक्षा बोर्ड यू.पी. द्वारा ली जाती थी ।

एक मिशनरी स्कूल भी भरतपुर शहर में चल रहा था । मैंने अपनी उम्र के तीसरे वर्ष से आठवें वर्ष तक की आरंभिक शिक्षा मिशनरी ऑफ चर्च की एक छोटी-सी पाठशाला में प्राप्त की । इस स्कूल का शिक्षक चर्च का पादरी था। पाठशाला में अंग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाएं सिखायी जाती थीं।

राज्य का एकमात्र आवासीय पब्लिक स्कूल नोबिल स्कूल के नाम से स्थापित हुआ जो कालान्तर में महाराजा बदनसिंह प्रिपेरेटरी स्कूल कहलाया । यह स्कूल केवल राज-सरदारों के बच्चों के लिए स्थापित हुआ था, जिसमें रियासत के सगे-संबंधी और कोठरी बंद ठाकुरों के ही बच्चे पढ़ सकते थे, उन्हें रियासत की तरफ से नि:शुल्क आवास एवं भोजन के अलावा पांच रुपया प्रति स्कालर वजीफा भी प्राप्त था। यह सिर्फ लड़कों का स्कूल था । राज्य के उच्च अधिकारियों के बच्चों को इसमें प्रवेश विशेष परिस्थितियों में मिल सकता था बशर्ते वे अधिकतम राशि फीस के रूप में दे सकें। अर्थात इन अन्य लोगों से तब 25/- रुपये फीस ली जाती थी ।

मुझे भी इस स्कूल में प्रवेश दिया गया लेकिन मेरे पिता ने ये 25/- रुपये न लेने का रियासत से आग्रह किया और कहा कि लवांनिया पुरोहित होने के लिहाज से हमें भी कोठरीबंद ठाकुरों में

गिना जाए । काफी जद्दोजहद के बाद हमारी प्रार्थना सुनी गई। मुझे खूब याद है जब रावराजा मानसिंह ने एक ऐसा छपा हुआ प्रलेख बताया जिसमें हमारी गणना चौबीस ठाकुरों में निर्धारित थी ।

निहायत साफ सुथरे इस स्कूल में कुल चार अध्यापक थे, एक यूरोपियन मैट्रन थी । महाराजा के यूरोपियन ट्यूटर कभी कभार इस स्कूल का निरीक्षण करते थे । निरीक्षण के दौरान वह कई इन्तजामों को देखते थे जैसे स्कूल का शिक्षण कक्ष, फर्नीचर, शिक्षण टूल्स के अलावा शिक्षण का स्तर, बच्चों की कक्षा में बैठने की मुद्रा, ड्रिल, हाइजीन, ड्रैस और हैबिट । फिर बोर्डिंग में नाश्ता और भोजन का स्तर, खाना बनाने वाले रसोइयों की स्वच्छता, काम और व्यवहार । बच्चों की दिनचर्या और कक्षा के अलावा पढ़ने की जिज्ञासा-यह सब वह यूरोपियन शख्स देखता था । अध्यापक सब देशज थे-कम से कम मैट्रिकुलेट अंग्रेजी सहित तो थे ही, कोई एकाध बी.ए. और एम .ए. तक पढ़ा लिखा होता था, लेकिन अल्पकालीन । शिक्षकों में ज्यादातर प्रशिक्षित नहीं थे । कुछ थे जिन्होंने संयुक्त प्रान्त से प्रारंभिक शिक्षण ट्रेनिंग ले रखी थी जो कुछ सप्ताह की होती थी। शिक्षण का तरीका पारंपरिक था। शिष्टाचार पर बहुत ध्यान दिया जाता था।

स्कूल की पाठ्यपुस्तकें डॉयरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शंस के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश के स्कूलों के मुताबिक थीं जिसमें अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, भूगोल, इतिहास, हाइजीन, ड्राइंग विषय थे। ये पाठ्यपुस्तकें उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) से खरीदी जाती थीं। बच्चों की ड्रेस थी सफेद कमीज, नीली पैन्ट और नीचे तक लटकता हुआ लहरिया का साफा। कमीज पर करीने से बांधी गई टाई खूब फबती थी । जाड़ों में ब्लेजर के कोट दिए जाते थे।

शिक्षण में अंग्रेजियत का थोड़ा-बहुत छोंक था लेकिन स्वदेशी साम्राज्यवादी जजबात कई तरह से महसूस होते थे । इसका नीचे दिया एक उदाहरण काफी है ।

रियासत के तमाम स्कूल आरंभ होने से पहले प्रार्थना बोलते थे, जैसा कि आम प्रचलन था कि विद्या-आरंभ ईश-प्रार्थना से किया जाए । यह प्रार्थना पहले उर्दू-फारसी में रौलअप फरमान में होती थी, बाद में यह हिन्दी में लिखकर रौलअप में चस्पा कर दी गई । प्रार्थना में चन्द पंक्तियों में कुछ इबारत इस तरह थी - ''ऐ परवरदिगार! पूरे खल्क के मालिक । हमें अच्छी तालीम से नवाज। ऐ परवरदिगार, हमारे राज और मुल्क के मालिक बर्तानिया सम्राट जार्ज पंचम को सलामत रख ...'' आदि-आदि कुल पांच छः पंक्तियों में यह प्रार्थना एक छात्र के द्वारा पढ़ी जाती और सभी उसे दुहराते थे । फिर विद्यार्थियों को कक्षाओं में पंक्तिबद्ध भेजा जाता।

स्कूल की पूरे दिन की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी - सुबह छः बजे बिस्तर छोड़कर नित्य नियम से फारिग होकर ड्रिल के लिए मैदान में इकट्ठा होना पड़ता था। नियमित ड्रिल के लिए ड्रिल मास्टर था। आठ बजे नाश्ता । नाश्ते में दूध था । मौसम के अनुसार हल्का खाद्य, फल आदि रहते थे । नौ बजे स्कूल, एक बजे मध्यान्ह भोजन, फिर आराम । शाम तीन से चार एक घंटा कक्षा, शाम की चाय, खेल और रात्रि भोजन और आराम। सुबह- शाम मैट्रन का निरीक्षण ।

महाराजा बदनसिंह पब्लिक स्कूल की स्मृतियां भी रोमांचक हैं । शाम गप-शप के दौरान तमाम तरह की बातें, बहस और क्रिया-कलाप होते थे । दरबार द्वारा पोषित राजखानदान के स्कॉलर आराम पसन्द तो होते ही थे लेकिन खेल और स्पोर्टस् के मैदान में वे सबसे आगे रहने का अभ्यास करते थे । खेलों में सब तरह के खेल खिलाड़ियों को उपलब्ध थे - हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, वॉलीवाल, बैडमिन्टन लोकप्रिय खेल थे । आपस में खूब स्नेह था, मौज-मस्ती के लिए स्कूल से बाहर भी ले जाया जाता था । जैसे राज्य के हर आयोजन में इस पब्लिक स्कूल के बच्चे अलग दिखाई देते थे- चाहे वह अवसर दशहरा सवारी का हो, नुमाइश में मनोरंजन का हो, होली-दशहरा का दरबार हो - हर आयोजन में साफाधारी बालक लोगों के लिए महकते फूल जैसे थे ।

इस स्कूल में पाँचवे स्टेन्डर्ड तक शिक्षा दी जाती थी । इसके बाद ऐंग्लों वर्नाक्यूलर और बाद में मैट्रिक में प्रवेश मिलता था। क्या थे वे दिन, क्या थे वे लोग-बसन्त के दिनों में खूब हुड़दंग रहता, होली आते-आते पूरा वातावरण मस्ती के रंग में डूब जाता । मैं कहूं कि मेरी नींव का पहला पत्थर यह स्कूल था, अतिशयोक्ति नहीं होगी ।◆

संदर्भ -

1. Proceedings of the central Advisory Committee Bharatpur State Sr No. 1 of 1939, under which president declared conslition reform and public welfare.

2. Birthday issue of Bharatpur Raj Parta EXtra-ordinary No. 2 1st Dec. 1943 (Declaration of Reforms)

3. Extract copy of Tour Notes of the President, Councel of Estate Bharatpur 22 October, 1933 Camp Sikri - Inspection of Primary School specially of Meo boys.

4. Annual Report on the Administration of Bharatpur State 1914-15, 1918-19, 1943-44.